भारत सरकार

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1976

जिसका उत्तर 11 फरवरी, 2026 को दिया जाना है ।

22 माघ, 1947 (शक)

सरकारी सेवाओं की अंतिम छोर तक सुपुर्दगी में सुधार पर डिजिटल प्लेटफॉर्मों का प्रभाव

1976. श्रीमती पूनमबेन माडमः

क्या **इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत पांच वर्षों के दौरान भारत की डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना को सुदृढ़ करने में डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत प्राप्त परिणामों का ब्यौरा क्या है;

(ख) विशेषकर ग्रामीण आबादी, महिलाओं और हाशिए पर रहने वाले समुदायों के लिए सरकारी सेवाओं के अंतिम छोर तक सुपुर्दगी में सुधार लाने में सरकार के डिजिटल प्लेटफार्मों का क्या प्रभाव पड़ा है; और

(ग) सरकार द्वारा राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों में डिजिटल इंडिया प्लेटफार्मो की अंतर-संचालनीयता, मापनीयता और भाषा की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद)

(क) से **(ग):** प्रौद्योगिकी का लोकतंत्रीकरण करने और नागरिकों को सशक्त बनाने के माननीय प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप, भारत सरकार ने जुलाई, 2015 में डिजिटल इंडिया कार्यक्रम शुरू किया था। समग्र लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि डिजिटल प्रौद्योगिकियां प्रत्येक नागरिक के जीवन में सुधार करें, भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था का विस्तार करें और भारत में निवेश और रोजगार के अवसर पैदा करें।

डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत, सरकार ने **खुले, इंटरऑपरेबल और स्केलेबल** प्लेटफार्मों के माध्यम से जनसंख्या पैमाने पर डिजिटल सेवाओं के वितरण को सक्षम करने के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (डीपीआई) दृष्टिकोण अपनाया है। डीपीआई सामान्य डिजिटल बिल्डिंग ब्लॉक्स प्रदान करता है जिसका सभी क्षेत्रों में पुन: उपयोग किया जा सकता है, जिससे सुरक्षा और पारस्परिकता सुनिश्चित करते हुए नागरिक-केंद्रित एप्लीकेशनों के तेजी से विकास को सक्षम बनाया जा सके।

डिजिटल सेवाओं में भाषाई समावेशन को बढ़ावा देने के लिए, सरकार **ने राष्ट्रीय भाषा अनुवाद मिशन (एनएलटीएम) - भाषिणी** शुरू किया है, जिसकी परिकल्पना भारतीय भाषा प्रौद्योगिकियों के लिए एक सार्वजनिक डिजिटल मंच के रूप में की गई है। भाषिणी मंच भारत की विविध आबादी के लिए संचार बाधाओं को दूर करता है। यह वंचित समुदायों के लिए डिजिटल उपकरणों तक अधिक पहुंच को बढ़ावा देता है। ओपन एपीआई नीति के कार्यान्वयन की सुविधा और सरकार भर में निर्बाध सेवा वितरण को सक्षम करने के लिए खुले और इंटरऑपरेबल डिजिटल प्लेटफॉर्म का निर्माण करने के लिए एपीआई सेतु प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। 7850+ एपीआई प्रकाशित किए गए हैं।

सरकार ने पहचान (आधार), भुगतान के लिए (यूपीआई), डेटा एक्सचेंज (डिजिलॉकर और एपीआई सेतु) आदि के लिए जनसंख्या पैमाने पर मूलभूत डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे (डीपीआई) को सफलतापूर्वक लागू किया है। डीपीआई भारत के सामाजिक-आर्थिक विकास में एक परिवर्तनकारी शक्ति रहा है, जो वित्तीय समावेशन, डिजिटल समावेशन, शासन और आर्थिक विकास में उल्लेखनीय वृद्धि करता है।

डिजिटल इंडिया पहल मोबाइल प्लेटफॉर्म के माध्यम से सुलभ है, जिसने शहरी-ग्रामीण विभाजन को पाटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वित्तीय समावेशन, डिजिटल समावेशन में सुधार और महिलाओं और वंचित वर्गों सहित समाज के सभी वर्गों के लिए आवश्यक सरकारी सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में डीपीआई का विस्तार करना भारत सरकार की एक प्रमुख प्राथमिकता रही है। ये पहल नागरिकों को कभी भी और कहीं से भी डिजिटल शिक्षा, डिजिटल स्वास्थ्य, डिजिटल भुगतान, ई-कोर्ट आदि जैसी सरकारी सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला तक पहुंचने में सक्षम बनाती हैं।

कुछ प्रमुख डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे (डीपीआई) और डिजिटल प्लेटफार्मों की स्थिति, जो विशेष रूप से ग्रामीण आबादी, महिलाओं और समाज के अन्य वर्गों के लिए सरकारी सेवाओं तक समावेशी और समान पहुंच सुनिश्चित करने में सहायक रहे हैं, इस प्रकार हैं:

- **आधार:** आधार दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल पहचान कार्यक्रम है जो बायोमेट्रिक और जनसांख्यिकीय-आधारित विशिष्ट डिजिटल पहचान प्रदान करता है। अब तक **143+ करोड़ आधार आईडी** तैयार की जा चुकी हैं।
- **यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई):** यूपीआई ने देश भर में डिजिटल लेनदेन में क्रांति ला दी है। यूपीआई ने ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में लाखों व्यक्तियों और छोटे व्यवसायों को तेज, सुरक्षित और कम लागत वाले डिजिटल भुगतान करने के लिए सशक्त बनाया है, जिससे वित्तीय समावेशन में काफी प्रगति हुई है। यूपीआई दुनिया की सबसे बड़ी भुगतान प्रणाली है।
  - यूपीआई 6.5 करोड़ व्यापारियों को सेवा प्रदान करता है और 685 बैंकों को एक मंच पर जोड़ता है, जिससे यह दुनिया की सबसे बड़ी डिजिटल भुगतान प्रणाली बन जाती है।
  - यूपीआई भारत के 81% डिजिटल भुगतान और वैश्विक वास्तविक समय के डिजिटल भुगतान के लगभग 49% को शक्ति प्रदान करता है।
- **डिजिलॉकर:** डिजिलॉकर ने आम नागरिक के लिए मूल जारीकर्ता से प्रामाणिक डिजिटल दस्तावेजों तक किसी भी समय पहुंच प्रदान की है। डिजिलॉकर की सेवाओं का लाभ उठाने के लिए **65.01 करोड़** से अधिक उपयोगकर्ता इसके साथ पंजीकृत हैं और प्लेटफॉर्म पर 2412 जारीकर्ताओं से 950+ करोड़ से अधिक दस्तावेज जारी किए गए हैं।
- नवीन शासन के लिए **एकीकृत मोबाइल एप्लिकेशन (उमंग**), सभी सरकारी सेवाओं के लिए एक ही मोबाइल एप्लिकेशन, परिचालन में है और यह व्यक्तियों के लिए **2390+ सेवाएँ** प्रदान करता है
- **ज्ञान साझा करने के लिए डिजिटल बुनियादी ढांचा (दीक्षा):** यह दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे विविध स्कूली शिक्षा मंच है। अब तक, दीक्षा का उपयोग करके 565.97 करोड़ शिक्षण सत्र आयोजित किए जा चुके हैं। इसने 18.47 करोड़ पाठ्यक्रम नामांकन और 14.69 करोड़ पाठ्यक्रम पूरे किए हैं।
- **सरकारी ई-मार्केटप्लेस (जीईएम):** जीईएम विभिन्न सरकारी विभागों/संगठनों/सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा आवश्यक सामान्य उपयोग की वस्तुओं और सेवाओं की ऑनलाइन खरीद की सुविधा प्रदान करता है। वर्तमान में, 168,345 प्राथमिक खरीदार और 243,666 द्वितीयक खरीदार जीईएम पर शामिल हैं। जीईएम पर 10,676 उत्पाद श्रेणियां और 354 सेवा श्रेणियां सूचीबद्ध हैं।
- **को-विन:** को-विन एक पारदर्शी प्रणाली है जो टीकाकरण सुविधाओं को आपूर्ति किए गए टीके की प्रत्येक खुराक की ट्रैकिंग की अनुमति देती है और बारीक स्तर पर मांग की पूर्ति को रिकॉर्ड करती है। टीकाकरण की 2.2+ बिलियन खुराक और उपयोगकर्ताओं के 1.11+ बिलियन पंजीकरण की सुविधा प्रदान की।
- **आरोग्य सेतु:** कोविड के प्रकोप की जांच और रोकथाम के लिए दुनिया का अग्रणी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग ऐप। आरोग्य सेतु बीमारी के फैलने की संभावना और संभावित हॉटस्पॉट की भविष्यवाणी करने में मदद करता है और डिजिटल स्वास्थ्य मूल्यांकन उपयोगकर्ता की वर्तमान स्वास्थ्य स्थिति पर अपडेट प्रदान करता है।
- **ई-संजीवनी** - भारत की राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन सेवा सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज (यूएचसी) प्राप्त करने के लिए डिजिटल स्वास्थ्य समानता की दिशा में एक कदम है। ई-संजीवनी स्मार्टफोन से डॉक्टरों और चिकित्सा

विशेषज्ञों तक त्वरित और आसान पहुंच की सुविधा प्रदान करती है। 18,447+ हब के माध्यम से 137,661 से अधिक स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों (प्रवक्ता के रूप में) में 44.70 करोड़ से अधिक रोगियों को टेलीमेडिसिन चिकित्सकों के रूप में 228,984 से अधिक डॉक्टरों, चिकित्सा विशेषज्ञों, सुपर-विशेषज्ञों और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं द्वारा सेवा प्रदान की गई।

- **ई-अस्पताल**-ई-अस्पताल एप्लिकेशन अस्पतालों के आंतरिक वर्कफ़्लो और प्रक्रियाओं के लिए अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली है। वर्तमान में, कुल 6,101 अस्पताल प्लेटफॉर्म पर सक्रिय और चालू हैं।
- **ई-कोर्ट:** ई-कोर्ट आईसीटी का उपयोग करके भारतीय न्यायपालिका को बदल रहा है। इसने न्यायिक और प्रशासनिक प्रक्रियाओं के इष्टतम स्वचालन को जन्म दिया है और यह इंटरऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम (आईसीजेएस) की रीढ़ है। 3680 से अधिक जिला और तालुका अदालत परिसरों को ई-कोर्ट प्लेटफॉर्म से जोड़ा गया है।
- **पोषण ट्रैकर:** यह महिलाओं और बाल विकास और पोषण सेवाओं के अंतिम मील वितरण के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है। यह लाभार्थियों और कर्तव्य वाहकों की वास्तविक समय की निगरानी और ट्रैकिंग प्रदान करता है और सक्रिय सेवा वितरण के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य कार्यक्रमों से जुड़ा हुआ है। 104 मिलियन लाभार्थियों को पोषण सेवाएं प्रदान की गई हैं, प्रभावी कार्यान्वयन और निगरानी सुनिश्चित करने के लिए 1.39 मिलियन आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा अंतिम छोर तक सेवा वितरण को डिजिटल रूप से ट्रैक किया जा रहा है।
- **ई-ऑफिस:** यह सरकारी कार्यालयों के लिए एक पूर्ण डिजिटल कार्यस्थल समाधान है जो विभागों को सूचित और त्वरित निर्णय लेने और कम कागजी कार्यालय में सहायता करता है। 1+ मिलियन उपयोगकर्ताओं के साथ 790 संगठनों में लागू किया गया और 53 मिलियन ई-फाइलों और 248+ मिलियन ई-रसीदों की सुविधा प्रदान की गई
- **एनसीडी प्लेटफॉर्म:** राष्ट्रीय गैर-संचारी रोग (एनसीडी) प्लेटफॉर्म प्राथमिक, सामुदायिक और जिला स्वास्थ्य सुविधाओं में उच्च रक्तचाप, मधुमेह और मुंह, स्तन और गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर सहित प्रमुख एनसीडी की स्क्रीनिंग, निदान और प्रबंधन की सुविधा प्रदान करता है। अब तक, 74.97 करोड़ लाभार्थियों को सिस्टम में नामांकित किया गया है और 8.64 करोड़ रोगियों का उच्च रक्तचाप और मधुमेह के लिए इलाज चल रहा है। यह प्लेटफॉर्म आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (एबीडीएम) के साथ एकीकृत है, जिसमें 11.94 करोड़ एबीएचए नंबर जेनरेट किए गए हैं/जुड़े हुए हैं।
- **एसआईडीएच (स्किल इंडिया डिजिटल हब):** कौशल और आजीविका के लिए डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र (डीईएसएच-स्टैक) नागरिकों के लिए एक सुलभ मंच में संपूर्ण कौशल पारिस्थितिकी तंत्र को एकीकृत करना। यह उपयोगकर्ताओं को डिजिटल युग में फलने-फूलने के लिए उपकरणों और संसाधनों के साथ सशक्त बना रहा है। इस प्लेटफॉर्म पर 17.32+ मिलियन उम्मीदवार पंजीकरण, 2.4+ मिलियन ऐप डाउनलोड और विभिन्न क्षेत्रों में 8500+ एनएसक्यूएफ और अकादमी पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं।
- **सामान्य सेवा केंद्र –** सीएससी ग्रामीण स्तर के उद्यमियों (वीएलई) के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में अंतिम मील कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए डिजिटल मोड में सरकारी और व्यावसायिक सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। सीएससी के माध्यम से **800 से अधिक सेवाएं** प्रदान की जा रही हैं। दिसंबर, 2025 तक, देश भर में (ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में) 5.87 लाख सीएससी कार्य कर रहे हैं, जिनमें से 4.57 लाख सीएससी ग्राम पंचायत स्तर (ग्रामीण) पर कार्य कर रहे हैं। सीएससी का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार और जिला-वार ब्यौरा https://csc.gov.in/ पर उपलब्ध है और सेवाओं की सूची https://csc.gov.in/ पर उपलब्ध है।
- **प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी):** डीबीटी सीधे कल्याणकारी भुगतान देने और नकली लाभार्थियों को हटाने के लिए आधार का उपयोग करता है। अब तक डीबीटी के माध्यम से 48+ लाख करोड़ रुपये हस्तांतरित किए जा चुके हैं। सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का अधिकांश वितरण डीबीटी के माध्यम से किया जा रहा है।
- **राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (एनएसपी):** यह मंच योजना के स्वामित्व वाले मंत्रालयों/विभागों और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) मोड के माध्यम से आवेदनों को संसाधित करने और छात्रवृत्ति/धन सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में वितरित करने में सक्षम बनाता है। राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (एनएसपी) 7.47 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को सेवा प्रदान करता है, जिसका कुल वितरण 44,181+ करोड़ रुपये से अधिक है। अब तक, 13 मंत्रालयों/विभागों और 21 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से संबंधित 153 स्कीमों को एनएसपी में शामिल किया गया है।

- **माईगव**: माईगव भारत सरकार का एक नागरिक जुड़ाव मंच है जो नीति निर्माण में लोगों को शामिल करने के लिए कई सरकारी निकायों/मंत्रालयों के साथ सहयोग करता है और सार्वजनिक हित और कल्याण के मुद्दों/विषयों पर लोगों की राय मांगता है। वर्तमान में, **6.08+ करोड़** से अधिक नागरिक माईगव के साथ पंजीकृत हैं, जो माईगव प्लेटफॉर्म पर आयोजित विभिन्न गतिविधियों में भाग ले रहे हैं।
- **जीवन प्रमाण:** जीवन प्रमाण एक आधार बायोमेट्रिक-सक्षम डिजिटल सेवा है जो केंद्रीय, राज्य और अन्य सरकारी पेंशनभोगियों को आधार-आधारित प्रमाणीकरण का उपयोग करके अपने घरों सहित भारत में कहीं से भी डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र (डीएलसी) आसानी से जमा करने की अनुमति देती है। 2014 से अब तक 11.96 करोड़ से अधिक डिजिटल जीवन प्रमाणपत्रों की प्रक्रिया की जा चुकी है।
- **पीएमजीदिशा:** प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान (पीएमजीदिशा) को देश भर में 6 करोड़ ग्रामीण परिवारों (प्रति परिवार एक व्यक्ति) में डिजिटल साक्षरता तक पहुंचाने के लिए शुरू किया गया था। देश भर में 6 करोड़ व्यक्तियों की तुलना में, 6.39 करोड़ व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया गया, जिससे यह दुनिया की सबसे बड़ी डिजिटल साक्षरता पहलों में से एक बन गई।
- **फ्यूचरस्किल्स प्राइम:** उद्योग कौशल अंतर को पाटने के लिए, एमईआईटीवाई ने नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज (नैसकॉम) के साथ संयुक्त रूप से "फ्यूचरस्किल्स प्राइम" नामक एक कार्यक्रम शुरू किया है, जिसका उद्देश्य नई/उभरती प्रौद्योगिकियों में उम्मीदवार को फिर से कौशल प्रदान करना है। फ्यूचरस्किल्स प्राइम कार्यक्रम के तहत, प्लेटफॉर्म पर 500+ से अधिक पाठ्यक्रम और 2000+ डिजिटल प्रवाह मार्ग पेश किए जाते हैं। 16.20+ लाख से अधिक उम्मीदवारों ने विभिन्न पाठ्यक्रमों में दाखिला लिया है, जिसमें लगभग 41 प्रतिशत महिला शिक्षार्थी शामिल हैं और 720 टियर -2 और टियर -3 शहरों के उम्मीदवारों ने नामांकन किया है।
- **लोकओएस एप्लिकेशन** को देश भर में स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) नेटवर्क के एंड-टू-एंड डिजिटलीकरण को सक्षम करने के लिए विकसित किया गया है। इसे वेब और मोबाइल दोनों प्लेटफार्मों के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिसमें प्रत्येक प्लेटफ़ॉर्म विशिष्ट परिचालन आवश्यकताओं के अनुरूप अलग-अलग उपयोगकर्ता प्रोफाइल और कार्यात्मकताओं का समर्थन करता है। 92 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को लोकओएस प्लेटफॉर्म पर पंजीकृत किया गया है, 5.56 लाख ग्राम संगठनों (वीओ) को प्रोफाइल किया गया है और इन समुदाय-आधारित संगठनों (सीबीओ) के माध्यम से जुटाए गए 10.23 करोड़ से अधिक परिवारों को डिजिटल रूप से प्रोफाइल किया गया है और लोकओएस पर जोड़ा गया है।

*****